गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 060
दि. 29.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

हवा में मौत का तांडव: फ्रांस में स्काईडाइविंग विमान और सऊदी में अरामको हेलिकॉप्टर हादसा, 25 लोगों की दर्दनाक मौत

रास तनुरा/टॉम्ब्लेन। रविवार का दिन दुनिया के दो देशों के लिए गहरे शोक का दिन बन गया। फ्रांस और सऊदी अरब में कुछ घंटों के अंतराल पर हुए दो भीषण हवाई हादसों ने 25 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। फ्रांस में स्काईडाइविंग के रोमांचक अनुभव के लिए उड़ान भरने वाला एक छोटा नागरिक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं सऊदी अरब के प्रमुख तेल केंद्र रास तनुरा में दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 14 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। दोनों घटनाओं के बाद संबंधित देशों में राहत एवं बचाव एजेंसियों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया है, जबकि हादसों के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत स्थित रास तनुरा में रविवार सुबह लगभग छह बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सऊदी अरामको का एक हेलिकॉप्टर उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि हेलिकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि हादसे में हेलिकॉप्टर पर मौजूद सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान सऊदी नागरिकों के रूप में हुई है।

रास तनुरा फारस की खाड़ी के तट पर स्थित सऊदी अरब का सबसे महत्वपूर्ण तेल एवं औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यहां स्थित तेल प्रतिष्ठान और निर्यात सुविधाएं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में हेलिकॉप्टर दुर्घटना होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को तत्काल घेर लिया। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और मलबे की जांच शुरू की। ऊर्जा मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे के

हर पहलू की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। फिलहाल हेलिकॉप्टर के मॉडल, उड़ान के उद्देश्य अथवा दुर्घटना के तकनीकी कारणों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या दुर्घटना का अरामको के तेल उत्पादन अथवा परिचालन पर कोई प्रभाव पड़ा है।

उधर यूरोप में फ्रांस के पूर्वी हिस्से में स्थित टॉम्ब्लेन शहर के निकट भी एक दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। नैंसी के पास स्काईडाइविंग के लिए उड़ान भरने वाला एक छोटा नागरिक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 11 लोग सवार थे और दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और चिकित्सा दल कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन तब तक विमान पूरी तरह तबाह हो चुका था।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विमान में सवार अधिकांश यात्री नैंसी क्षेत्र में कार्यरत नर्स थे, जिन्होंने पहली बार स्काईडाइविंग का अनुभव लेने के लिए यह विशेष यात्रा बुक की थी। छुट्टी के दिन रोमांच और उत्साह से भरी यह यात्रा कुछ ही पलों में दर्दनाक त्रासदी में बदल गई। बताया जा रहा है कि विमान ने उड़ान सामान्य रूप से शुरू की थी, लेकिन कुछ समय बाद वह नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज धमाके की आवाज सुनने और उसके बाद धुएं का गुबार उठते देखने की बात कही है। घटना की सूचना मिलते ही स्वतंत्र नर्स संगठन की स्थानीय शाखा के प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

फ्रांसीसी विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति, इंजन फेल होने या मानवीय त्रुटि जैसे सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। विमान के फ्लाइट रिकॉर्ड और तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने लाई जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हाल के वर्षों में फ्रांस के सबसे गंभीर छोटे विमान हादसों में से एक है।

दो अलग-अलग देशों में हुए इन हादसों ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर अत्याधुनिक तकनीक से लैस औद्योगिक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो दूसरी ओर रोमांचक खेल के लिए उड़ान भरने वाला नागरिक विमान भी सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंच सका। दोनों घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक विमानन व्यवस्था में सुरक्षा मानकों की लगातार समीक्षा और तकनीकी निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

फिलहाल दोनों देशों की जांच एजेंसियां दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन हादसों की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकेगी। वहीं इन दो त्रासदियों ने 25 परिवारों को ऐसा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होगी। रविवार का दिन उन परिवारों के लिए हमेशा एक ऐसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब आसमान की ओर उठी उड़ानें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मौत की खामोशी में बदल गईं।

गुटखा-पान मसाला पर कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन! नशीले तत्व मिले तो पूरे राज्य में लगेगा प्रतिबंध, सीएम शिवकुमार की दोटूक चेतावनी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और पान मसाला कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि जांच में गुटखा या पान मसाला उत्पादों में नशीले पदार्थ मिलाए जाने की पुष्टि होती है, तो पूरे राज्य में ऐसे उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि युवाओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकार इस मामले में "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाएगी।

रविवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 31वें स्थापना दिवस तथा बेंगलुरु में आयोजित 'नशा मुक्त भारत सम्मेलन' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ ऐसे इनपुट प्राप्त हुए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि बाजार में बिक रहे कुछ पान मसाला और गुटखा उत्पादों में नशे की लत पैदा करने वाले तत्व मिलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक जांच में इन आशंकाओं की पुष्टि होती है, तो सरकार ऐसे उत्पादों को राज्यभर में पूरी तरह प्रतिबंधित करने में कोई देर नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला दायित्व लोगों, विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

उन्होंने चिंता जताई कि तंबाकू उत्पादों का सेवन पहले से ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है और यदि उनमें अतिरिक्त नशीले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

अपने संबोधन में डी.के. शिवकुमार ने मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाकर नशे की समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसके लिए समाज, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा समुदाय और युवाओं को मिलकर जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे इनपुट मिले हैं कि अब पान मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों में भी नशा पैदा करने वाले तत्व मिलाए जा रहे हैं। यदि जांच में किसी भी उत्पाद में थोड़ी सी भी नशीली सामग्री पाई गई, तो कर्नाटक में उसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।"

सरकार के अनुसार संबंधित विभागों और जांच एजेंसियों को इन उत्पादों के नमूनों की जांच करने तथा उनकी गुणवत्ता और संरचना का परीक्षण करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। यदि किसी उत्पाद में प्रतिबंधित या नशीले रसायनों की मौजूदगी पाई जाती है, तो उसके निर्माण, बिक्री और वितरण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े लोगों की भी जवाबदेही तय की जा सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, हृदय रोग, दांतों की गंभीर समस्याओं और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यदि इनमें अतिरिक्त नशीले तत्व मिलाए जाते हैं, तो इनके सेवन की लत और अधिक गहरी हो सकती है, जिससे विशेष रूप से युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है।

कर्नाटक सरकार का यह सख्त रुख ऐसे समय सामने आया है, जब देशभर में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें, अपने परिवार और बच्चों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें तथा स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग दें।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बड़ा बदलाव: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी सेवानिवृत्त, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा बने नए सदस्य

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के साथ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नया स्वरूप सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे.के. माहेश्वरी रविवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद कॉलेजियम में उनकी जगह जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने ले ली है। इस बदलाव के साथ देश की न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण निकाय की संरचना भी बदल गई है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारतीय न्यायपालिका की वह सर्वोच्च संस्था है, जो उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी सिफारिशें करती है। इसलिए कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका न्यायपालिका की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जस्टिस माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद अब जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा इस पांच सदस्यीय निकाय का हिस्सा बन गए हैं। वरिष्ठता क्रम के अनुसार वह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पांचवें सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और नियमों के मुताबिक वे 2 मई 2028 तक कॉलेजियम के सदस्य बने रहेंगे। इसी दिन उनका सेवानिवृत्ति का निर्धारित समय भी है।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने लगभग पांच वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और न्यायिक प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णयों में भागीदारी निभाई। कॉलेजियम के सदस्य के रूप में भी उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाई। उनकी विदाई के साथ न्यायपालिका के एक अनुभवी अध्याय का समापन हुआ है।

दूसरी ओर, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा का कॉलेजियम में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्हें संवैधानिक और विधिक मामलों का गहरा अनुभव प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने से पहले वे देश के प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते थे और कई संवैधानिक मामलों में पक्षकारों की ओर से प्रभावी पैरवी कर चुके हैं। न्यायिक सेवा में आने के बाद भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में अपनी स्पष्ट कानूनी दृष्टि और संतुलित निर्णयों से अलग पहचान बनाई है।

जस्टिस माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नई टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। वरिष्ठता के आधार पर गठित यह टीम आने वाले समय में देशभर के उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेगी।

वर्तमान समय में न्यायपालिका के सामने लंबित मामलों का बढ़ता बोझ, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना तथा न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में नए कॉलेजियम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने, नई नियुक्तियों को गति देने और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में यह कॉलेजियम महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में यह बदलाव न्यायपालिका की नियमित संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण है कि कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य के बदलाव पर न्यायिक जगत, विधि विशेषज्ञों और कानूनी समुदाय की विशेष नजर रहती है। अब सभी की निगाहें नई टीम पर हैं, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, दक्षता और गति बनाए रखने की अपेक्षा की जा रही है।

एमडीएमके में बड़ी टूट, 150 से ज्यादा नेताओं ने थामा डीएमके का दामन, तमिलनाडु की सियासत में नए समीकरणों के संकेत

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में रविवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के 150 से अधिक वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, छात्र नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह राजनीतिक बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब महज एक दिन पहले ही एमडीएमके की सामान्य परिषद ने पार्टी संस्थापक वाइको के नेतृत्व में डीएमके से अपना वर्षों पुराना गठबंधन समाप्त करने का फैसला लिया था। ऐसे में गठबंधन टूटने के तुरंत बाद इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का डीएमके में शामिल होना तमिलनाडु की राजनीति में दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है।

चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की मौजूदगी में इन नेताओं ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया और विश्वास जताया कि इन नेताओं के आने से संगठन को राज्य के विभिन्न जिलों में और अधिक मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल दल-बदल नहीं, बल्कि तमिलनाडु के विपक्षी राजनीतिक समीकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी है।

डीएमके में शामिल होने वालों में एमडीएमके के कई प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं। शिवगंगा जिले के वरिष्ठ नेता पुलावर एस. सेवन्थियप्पन, तिरुवल्लूर के टी.आर.आर. सेंगुट्टुवन, पार्टी के प्रचार सचिव तिरुपरंकुंद्रम अलगुसुंदरम तथा विरुधुनगर के आर.एम.एस. शेखर जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ डीएमके की सदस्यता ली। इनके अलावा जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य, छात्र संगठन के प्रतिनिधि और बड़ी

संख्या में कार्यकर्ता भी डीएमके में शामिल हुए। माना जा रहा है कि इन नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा जनाधार है, जिससे डीएमके को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवगंगा, तिरुवल्लूर, विरुधुनगर और तिरुपुर जैसे जिलों में इन नेताओं का प्रभाव लंबे समय से रहा है। ऐसे में इनके डीएमके में आने से पार्टी की संगठनात्मक पकड़ और मजबूत होगी। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तथा भविष्य के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी यह घटनाक्रम डीएमके के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन विस्तार की रणनीति के तहत डीएमके लगातार विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है और इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को उसी दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

इस राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर एमडीएमके पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी पहले ही गठबंधन समाप्त करने के फैसले के बाद नई राजनीतिक दिशा तय करने की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे समय में बड़ी संख्या में नेताओं का पार्टी छोड़ना संगठन के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर झटका माना जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे एमडीएमके की संगठनात्मक क्षमता और जनाधार पर असर पड़ सकता है, जबकि पार्टी नेतृत्व फिलहाल इस घटनाक्रम पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है।

छात्र राजनीति में भी डीएमके को बड़ी सफलता मिली है। तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के लगभग 40 छात्रों ने भी डीएमके की सदस्यता ग्रहण की। इन छात्रों का संबंध एमडीएमके के छात्र संगठन से माना जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि युवा वर्ग का किसी राजनीतिक दल की ओर झुकाव भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। डीएमके लंबे समय से युवाओं और छात्रों को संगठन से जोड़ने के अभियान पर काम कर रही है और यह घटनाक्रम उसी रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। डीएमके नेतृत्व ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, विकास और जनकल्याण की अपनी नीतियों के कारण लगातार लोगों का विश्वास जीत रही है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता डीएमके की नीतियों से प्रभावित होकर स्वेच्छा से संगठन से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु के विकास और सामाजिक समानता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी सभी वर्गों का स्वागत करती रहेगी।

दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमडीएमके द्वारा गठबंधन समाप्त करने के निर्णय के तुरंत बाद इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का डीएमके में शामिल होना कई राजनीतिक सवाल भी खड़े करता है। कुछ विशेषज्ञ इसे एमडीएमके के भीतर लंबे समय से चल रही असंतुष्टि का परिणाम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए लिया गया रणनीतिक निर्णय हो सकता है। हालांकि, इसके वास्तविक कारणों का स्पष्ट आकलन आने वाले दिनों में ही हो सकेगा।

तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और उसके सहयोगियों का लंबे समय से मजबूत प्रभाव रहा है। ऐसे में विपक्षी दल लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमडीएमके में हुई इस बड़ी टूट ने विपक्षी खेमे की रणनीति को झटका दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह नेताओं का पलायन जारी रहा, तो विपक्षी दलों के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एक ओर डीएमके इसे अपनी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव और बदलते समीकरणों का परिणाम मान रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि एमडीएमके इस राजनीतिक झटके से किस तरह उबरती है और डीएमके इस नए संगठनात्मक विस्तार का कितना लाभ उठा पाती है। इतना तय है कि 150 से अधिक नेताओं का एक साथ पार्टी बदलना केवल एक सामान्य दल-बदल नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

संपादकीय

आग की राजनीति और लोकतंत्र की तपिश

आग केवल लकड़ी, ईंधन या मकानों को ही नहीं जलाती, वह कई बार व्यवस्था की सच्चाइयों को भी उजागर कर देती है। इतिहास गवाह है कि आग का इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्ता, स्वार्थ और नियंत्रण के औजार के रूप में भी होता रहा है। कभी किसी बस्ती में आग लगती थी, कभी सरकारी दफ्तरों में महत्वपूर्ण फाइलें जल जाती थीं और आज के दौर में कभी किसी गोदाम, कभी किसी फैक्ट्री, तो कभी चुनावी उपकरणों में आग लगने की खबरें सामने आ जाती हैं। हर घटना के बाद एक ही सवाल उठता है—क्या यह केवल संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो राख के नीचे दब जाती है? एक समय था जब गर्मियों के मौसम में झुग्गी-बस्तियों में आग लगने की खबरें लगभग हर वर्ष सुनने को मिलती थीं। कारण अक्सर शॉर्ट सर्किट, चूल्हे की चिंगारी या तेज हवा को बताया जाता था। लेकिन इन घटनाओं के बाद जिस तेजी से उन जमीनों पर नए निर्माण शुरू होते थे, उसने लोगों के मन में अनेक सवाल पैदा किए। जिन जगहों पर कभी गरीबों की झोपड़ियां थीं, वहां कुछ वर्षों में आलीशान इमारतें, मॉल, व्यावसायिक परिसर और महंगे आवास खड़े दिखाई देने लगे। यह संयोग था या योजनाबद्ध विकास का कठोर चेहरा, इसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। समय बदला तो तस्वीर भी बदली। अब केवल झुग्गियां ही नहीं, बल्कि बहुमंजिला इमारतें, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आग लगने लगी। हर घटना के बाद जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं और सुरक्षा मानकों पर लंबी चर्चाएं होती हैं। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब तक कि अगली आग किसी नई जगह पर न लग जाए। ऐसा लगता है जैसे हमारी व्यवस्था हर दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक जागती है और फिर धीरे-धीरे उसी पुरानी नींद में लौट जाती है।

सरकारी दफ्तरों में आग लगने की घटनाएं भी हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। जब किसी महत्वपूर्ण विभाग में आग लगती है और उसके साथ वर्षों पुराने दस्तावेज तथा रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं, तब संदेह स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। अनेक बार भ्रष्टाचार, अनियमितताओं या विवादित मामलों से जुड़ी फाइलों के नष्ट होने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि हर मामले में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या दुर्घटना ही बताया जाता है, लेकिन जनता के मन में यह प्रश्न बना रहता है कि आखिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों होती है। डिजिटल युग में भी यदि रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रह पाते, तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी प्रश्न बन जाता है। हाल के वर्षों में कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े उपकरणों या सामग्री के क्षतिग्रस्त होने अथवा आग लगने की खबरों ने भी बहस को जन्म दिया है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ऐसे में यदि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं। इन शंकाओं का समाधान केवल निष्पक्ष जांच, पारदर्शी सूचना और समयबद्ध कार्रवाई से ही संभव है। लोकतंत्र केवल निष्पक्ष चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने से भी मजबूत होता है। आज की राजनीति में आग केवल वास्तविक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी हो गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक टकराव भी समाज में ऐसी मानसिक आग पैदा कर रहे हैं, जो कई बार किसी वास्तविक आग से अधिक खतरनाक साबित होती है। शब्दों की चिंगारी कई बार सड़कों तक पहुंच जाती है और उसका नुकसान वर्षों तक समाज को झेलना पड़ता है। इसलिए जिम्मेदार राजनीति और संयमित सार्वजनिक संवाद आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं।

यह भी सच है कि हर आग के पीछे षड्यंत्र तलाशना उचित नहीं होता। बिजली की खराब व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी, अवैध निर्माण, जर्जर वायरिंग और प्रशासनिक लापरवाही भी अनेक हादसों के प्रमुख कारण हैं। लेकिन जब बार-बार एक जैसी घटनाएं सामने आती हैं और जांच के परिणाम वर्षों तक स्पष्ट नहीं हो पाते, तब लोगों के मन में अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है, और यदि वही कमजोर पड़ने लगे तो किसी भी व्यवस्था के लिए यह शुभ संकेत नहीं माना जा सकता।

राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाता दल-बदल

> दलबदल से बचने के लिए जरूरी है कि दल-बदल कानून को मजबूत बनाया जाये। पहली जरूरत तो यह है कि दल-बदल करने वालों को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की शर्त हो। निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल का मतलब मतदाताओं को धोखा देना ही है। नैतिकता का तकाजा है कि वे दल बदलना चाहते हैं तो पद से त्यागपत्र दें।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फिर टूट गई है। पहले चालीस विधायकों ने बगावत की थी और अब उद्धव के छह सांसद पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं। एक को छोड़कर बाकी पांच ने यह कदम उठाने का कारण बताते हुए मूल शिवसेना की नीति-रीति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस का साथ दिया है, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनसे पूछा जाना चाहिए जब शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने उद्धव का दामन छोड़ा था, तब भी तो यही स्थिति थी। तब उन्होंने शिंदे का साथ क्यों नहीं दिया? अब भाजपा में जाने वाले इन सांसदों ने अपने इस कदम उठाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। हां, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े बचे-खुचे 'शिवसैनिकों' ने यह आरोप अवश्य लगाया है कि भाजपा ने उन्हें 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक की 'रिश्वत' देकर शिवसेना को तोड़ा है।

यह पहली बार नहीं है जब दल-बदलू राजनीति का बदरंग चेहरा सामने आया है। देश में 'आयारामों -गयारामों' की एक लंबी सूची है। दल-बदलुओं की यह कथा लगभग छह दशक पहले शुरू हुई थी। कहानी अब भी जारी है। तब भी दल-बदल के पीछे कारण कोई सिद्धांत या नीति नहीं थी और अब भी दिखाई यही दे रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ ही इस जनतंत्र-विरोधी कार्रवाई का मूल कारण है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमारे राजनेता इस स्तर तक जायेंगे, पर आज यह स्थिति एक खुली किताब की तरह सामने है। न दल बदलने वालों को शर्म आती है और न दल बदल करवाने वालों को।

हां, पिछले लगभग एक दशक से देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है– मूल्यों- सिद्धांतों को ताक में रखकर किसी भी कीमत पर राजनीतिक लाभ उठाने वाला अध्याय। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था- कांग्रेस मुक्त भारत अभियान। सत्ता में आने के साथ ही भाजपा ने अपने इस सपने को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी थी। और उसे कुछ सफलता भी मिलने लगी थी। पार्टी का हौसला बढ़ गया। इस हौसले के सामने सही-ग़लत कोई माने नहीं रखता था। वैसे भी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती, पर राजनीति के इस नये दौर में सब कुछ जायज था। इस रीति-नीति के परिणामस्वरूप 'वाशिंग मशीन' वाली राजनीति ने रंग दिखाना शुरू किया। राजनेताओं पर आरोप लगने या अपराध स्पष्ट हो जाने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। जो हमारे साथ है वह सही है वाली यह राजनीति किसी भी कीमत पर अपने उद्देश्य को पूरा करने में विश्वास करती है। सत्ता पाना और सत्ता पर बने रहना ही जैसे राजनीति का एकमात्र उद्देश्य हो! खतरनाक है यह स्थिति और सबसे बड़ा खतरा जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर है। देश की राजनीति का जो अध्याय आज लिखा जा रहा है, वह सिर्फ सत्ता हथियाने की या सत्ता में बने रहने के प्रयासों की कहानी ही नहीं है, खतरे में हमारा लोकतंत्र है। यह अध्याय 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे से शुरू हुआ था, अब वह 'विपक्ष मुक्त भारत' की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह आज छोटे और क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है, वह जनतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'लाउड एंड क्लियर' यानी पूरी तरह स्पष्ट। इसे अनदेखा या अनसुना करना जनतंत्र के प्रति अपने दायित्व से मुंह चुराना ही है।

मजबूत विपक्ष जनतंत्र के औचित्य और सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। मज़बूत सरकार की तरह ही एक सुदृढ़ विपक्ष भी चाहिए होता है। कमजोर विपक्ष का मतलब होता है एक ऐसी सरकार को अवसर और छूट देना जो कभी भी तानाशाही का रास्ता अपना सकती है। आप चाहें तो इसे निर्वाचित तानाशाही कह सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए जागरूक मतदाता की आवश्यकता है जो जनतंत्र की सफलता में मजबूत विपक्ष की महत्ता और आवश्यकता को समझे और ऐसी किसी भी कार्रवाई के प्रति सजग रहे जो जनतंत्र को कमजोर बनाती है। आज जिस तरह छोटे राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अप्रासंगिक बनाने का प्रयास हो रहा है, उससे हमारा जनतंत्र कमज़ोर ही होगा। हाल ही के दिनों में हुई दल-बदल की घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अजनतांत्रिक ताकतें लगातार सक्रिय हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसदों को दल-बदल करके भाजपा की शरण में जाते देखा था। फिर हमने देखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पराजय के बाद उसके विधायकों और सांसदों ने दल-बदल करना जरूरी समझ लिया। नवीनतम उदाहरण महाराष्ट्र में टूटी हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी को और तोड़ने का है। जैसी स्थितियां बन रही हैं, उनसे इस आशय के संकेत भी मिल रहे हैं कि टूटने-बिखरने का खतरा शरद पवार की एनसीपी को भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री इस आशय के संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोशलिस्ट पार्टी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत भी घटा दी गयी है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

यह सब घटनाएं बताती हैं कि किस तरह देश में विपक्ष को कमज़ोर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। विपक्ष के कमज़ोर होने का मतलब जनतंत्र का कमज़ोर होना है और जनतंत्र कमज़ोर होता है तो तानाशाही प्रवृत्तियों को सिर उठाने का अवसर मिल जाता है।

देश में केंद्र में मज़बूत सरकार हो, यह एक अच्छी स्थिति है। इसी तरह राज्यों में सरकारें ताकतवर हों, इसमें भी कहीं कुछ ग़लत नहीं है। पर यह मजबूती और ताकत जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में मज़बूत सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह जनतांत्रिक परंपराओं को, जनतांत्रिक मूल्यों को पनपाने के प्रति भी सावधान रहे।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो संसद में विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर थी। कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई थीं। विपक्ष को मिली कुल 125 सीटों में सबसे बड़ा दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे मात्र 16 सीटें मिली थीं। भारतीय जन संघ के हिस्से में सिर्फ तीन सीटें आयी थीं। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा था, चूंकि विपक्ष सदन में कमज़ोर है, इसलिए उन्हें ही विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी। अर्थात् सरकार के काम-काज पर नजर रखनी होगी। पहले प्रधानमंत्री का यह कथन जनतांत्रिक मूल्यों में तो उनके विश्वास और आस्था को दर्शाता ही है, यह भी बताता है कि वे जनतंत्र की सफलता के लिए ताकतवर विपक्ष की उपस्थिति को कितना ज़रूरी समझते थे।

लेकिन आज स्थिति बदल गयी है। सत्तारूढ़ पक्ष येन-केन प्रकारेण विपक्ष को कमज़ोर बनाना चाहता है। दल-बदल को बढ़ावा देने वाले 'आपरेशन लोटस' अथवा 'आपरेशन टाइगर' जैसे प्रयास यही बताते हैं। ऐसे प्रयासों को विफल बनाना ज़रूरी है, ताकि जनतंत्र जिंदा रहे।

दलबदल से बचने के लिए जरूरी है कि दल-बदल कानून को मज़बूत बनाया जाये। पहली ज़रूरत तो यह है कि दल-बदल करने वालों को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की शर्त हो। निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल का मतलब मतदाताओं को धोखा देना ही है। नैतिकता का तकाज़ा है कि वे दल बदलना चाहते हैं तो पद से त्यागपत्र दें। फिर से चुनाव लड़ें। पता नहीं दल-बदल कानून बनाते समय यह बात क्यों छोड़ दी गयी थी। अब जोड़ा जाना चाहिए इसे। पर यह होगा कैसे? जो यह कर सकते हैं, वे स्वयं दल-बदल को बढ़ावा देने वाले हैं! पर कुछ तो होना ही चाहिए– मुद्दा जनतंत्र को जीवित रखने का है!

प्रेरणा

जब पहाड़ चुप थे और यादें बोल रही थीं

कभी-कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है, जहाँ पहुँचकर लगता है कि हम किसी शहर में नहीं, बल्कि अपनी ही स्मृतियों के भीतर प्रवेश कर गए हैं। वर्षों तक मन में संजोई हुई कोई मुलाकात जब अचानक सच बन जाती है, तब समय का लंबा अंतराल भी कुछ क्षणों में सिमट जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पुराने मित्र के निमंत्रण पर मैं पहली बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे-से नगर पहुँचा। वहाँ की हवा में ऐसी ताजगी थी जिसे शब्दों में बाँधना आसान नहीं। देवदार के वृक्ष बादलों से बातें कर रहे थे, पहाड़ों की ढलानों पर बने घर किसी चित्रकार की कल्पना जैसे लग रहे थे और दूर-दूर तक फैली हरियाली मन को भीतर तक शांत कर रही थी।

स्टेशन से बाहर निकलते ही वह मेरा इंतजार करती मिलीं। लगभग पच्चीस वर्षों बाद आमने-सामने मुलाकात हो रही थी, लेकिन पहचानने में किसी को एक पल भी नहीं लगा। चेहरे पर उम्र की हल्की रेखाएँ थीं, पर मुस्कान वैसी ही सहज थी जैसी कभी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। हमने हाथ मिलाया, फिर बिना किसी औपचारिकता के बातचीत शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे बीच के वर्षों ने केवल कैलेंडर बदला है, रिश्ते की गर्माहट नहीं।

उनका घर शहर से थोड़ा दूर एक पहाड़ी ढलान पर था। सफेद रंग की दीवारें, लाल छत, लकड़ी की बालकनी और सामने छोटे-छोटे फूलों की कतारें। घर के पीछे घना जंगल था, जहाँ से लगातार पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जिसमें शोर भी मधुर लगने लगता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह घर छोटा है, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शांति यहीं मिलती है।" उनकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि किसी घर की विशालता उसके कमरों से नहीं, उसमें बसने वाले अपनत्व से तय होती है।

दोपहर धीरे-धीरे शाम में बदल रही थी। अचानक बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों की बारिश का अपना अलग ही स्वभाव होता है। वह केवल भीगाती नहीं, बल्कि वातावरण को धुला हुआ बना देती है। मैंने होटल जाने की बात की तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि इस मौसम में बाहर निकलना समझदारी नहीं होगी। मित्र इतने वर्षों बाद मिले हैं, तो एक शाम साथ बिताने में क्या संकोच। उनके आग्रह में इतनी आत्मीयता थी कि इंकार करना असंभव था।

थोड़ी देर बाद रसोई से मसालों वाली चाय की सुगंध पूरे घर में फैल गई। गरम पकौड़ों के साथ चाय पीते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हमने पुराने दिनों की शरारतें याद कीं, उन मित्रों का जिक्र किया जो अब अलग-अलग शहरों में बस चुके थे और उन सपनों की भी चर्चा हुई जिन्हें कभी साथ बैठकर देखा था। समय ने सबको बदल दिया था, लेकिन स्मृतियाँ अभी भी वैसी ही ताजा थीं।

धीरे-धीरे बातचीत वर्तमान जीवन तक पहुँच गई। उन्होंने बताया कि जीवन बाहर से जितना व्यवस्थित दिखाई देता है, भीतर से हमेशा वैसा नहीं होता। परिवार, जिम्मेदारियाँ और सामाजिक अपेक्षाएँ कई बार इंसान को मुस्कुराने की आदत तो सिखा देती हैं, लेकिन खुलकर जीने का अवसर नहीं देतीं। उन्होंने कहा कि एक स्त्री को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान और विश्वास की होती है। यदि उसके निर्णयों का मूल्य न रहे, तो उसका आत्मविश्वास धीरे-धीरे कम होने लगता है। उनके शब्दों में शिकायत कम और अनुभव की सच्चाई अधिक थी। बैठक में रखी तस्वीरों पर मेरी नजर गई। एक फोटो में उनके माता-पिता थे। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए कहा कि माँ उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थीं। बचपन की छोटी-छोटी बातें याद करते हुए उनकी आँखें भर आईं। उन्होंने बताया कि माँ हर कठिन समय में उनका हाथ थाम लेती थीं। आज भी जब जीवन उलझता है, सबसे पहले माँ की याद आती है। कुछ रिश्ते समय से नहीं टूटते, केवल दिखाई देना बंद हो जाते हैं।

रात का भोजन सादगी से भरा था। स्थानीय सब्जियाँ, गरम रोटियाँ और घर का बना हुआ सादा भोजन। भोजन के बाद हम बरामदे में बैठ गए। सामने बादलों के बीच कभी-कभी बिजली चमक जाती और पूरा जंगल एक क्षण के लिए उजाले में नहा उठता। अचानक रात लगभग दो बजे एक अनजानी आवाज सुनाई दी। वह किसी पक्षी की थी, लेकिन उसमें ऐसी करुणा थी कि सुनते ही मन विचलित हो जाए। आवाज बार-बार उसी पुराने पेड़ से आ रही थी जो घर के पीछे खड़ा था।

मैंने उत्सुकता से पूछा कि यह कौन-सा पक्षी है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से यह आवाज सुनाई देती है, पर आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि यह किसकी पुकार है। कुछ लोग इसे पहाड़ी पक्षी कहते हैं, कुछ लोककथा से जोड़ते हैं और कुछ इसे केवल प्रकृति का रहस्य मानते हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि जब भी यह आवाज सुनती हूँ, मुझे अपनी एक प्रिय रिश्तेदार की याद आ जाती है, जो महामारी के दिनों में अचानक दुनिया छोड़ गई। पता नहीं क्यों, उस पक्षी की पुकार में मुझे हमेशा वही अधूरापन सुनाई देता है।

उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद हर मनुष्य अपने भीतर किसी न किसी आवाज को जीवन भर ढोता रहता है। किसी के लिए वह बिछड़ते रिश्तों की प्रतिध्वनि होती है, किसी के लिए अधूरे सपनों की और किसी के लिए खोए हुए अपनों की स्मृति। प्रकृति कभी-कभी उन भावनाओं को व्यक्त कर देती है जिन्हें मनुष्य शब्दों में नहीं कह पाता।

रात गहराती चली गई, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। बाहर जंगल शांत था, फिर भी उस रहस्यमयी पुकार की गूँज भीतर तक उतर रही थी। मुझे लगा कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी अकेलापन नहीं, बल्कि वह स्थिति है जब हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ हो और सुनने वाला कोई न मिले। शायद इसलिए कुछ लोग पहाड़ों में आकर बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़, बादल, बारिश और हवा बिना किसी निर्णय के हर दर्द को सुन लेते हैं।

सुबह जब विदा लेने का समय आया तो वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। रात की बारिश के बाद पहाड़ धुले हुए दिखाई दे रहे थे।

एआई संप्रभुता की ओर बढ़े भारत

ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर एंथ्रोपिक के सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फेबल 5 और मिथोस 5 के विदेशी उपयोग पर प्रतिबंध ने सभी को सकते में डाल दिया है। आदेश के अनुसार विदेश में कार्यरत अमेरिकी भी एंथ्रोपिक के इन टूल्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

एंथ्रोपिक के अनुसार जो प्रमाण दिखाए गए हैं, वे इतने व्यापक प्रतिबंध को उचित नहीं ठहराते, पर उसके पास सरकारी निर्देश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जानकारों का मानना है कि एंथ्रोपिक को ट्रंप प्रशासन के उस पूर्वाग्रह की कीमत चुकानी पड़ रही है, जो एंथ्रोपिक के मुकाबले ओपन एआई को लाभान्वित करना चाहती है।

बहरहाल इस स्थिति ने भारत समेत विश्व भर के उन एआई डेवलपर्स के लिए कठिनाई खड़ी कर दी है, जो इन टूल्स पर निर्भर थे। इस कदम ने ऐसे भय को जन्म दिया है, जो भविष्य में भारत की तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस स्तर पर कृषि से उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित होना चाहिए था, उसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, परंतु आइटी क्षेत्र में हुए विस्तार ने न केवल इस नुकसान की भरपाई की, बल्कि अर्थव्यवस्था को बल भी दिया। तार्किक रूप से आइटी का विकास न केवल एआई के विस्तार की ओर जाएगा, बल्कि कोडिंग, डाटा एंट्री, मैन्युअल टेस्टिंग और पासवर्ड रीसेट सरीखे लेवल 1 और 2 आइटी सपोर्ट जैसे कार्यों को हटाकर उनका स्थान भी ले लेगा।

एआई प्रतिस्पर्धा में कौन देश कितनी बढ़त बनाएगा, यह वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ यह भी तय करेगा कि उसका सरकारी एवं गैर सरकारी तंत्र कितना स्वतंत्र या परतंत्र रहेगा। एआई क्षेत्र या डाटा पर विदेशी निर्भरता अर्थतंत्र, राजनीति, शासन-प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता जैसे राष्ट्र जीवन के तमाम पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत एआई और डाटा क्षेत्र में यथाशीघ्र संप्रभुता प्राप्त करे। भारत ने अब तक ऐसे संदेश दिए हैं, जिसमें वह छोटे परंतु विशिष्ट एआई माडल्स या एप्लिकेशंस बनाने को प्राथमिकता देगा। संप्रभु एआई किसी देश की वह क्षमता है, जिसके तहत वह घरेलू आधारभूत ढांचे, स्थानीय डाटा, मानवीय प्रतिभा और कानूनी ढांचे का प्रयोग कर एआई सिस्टम्स को विकसित, लागू और नियंत्रित कर सकता है।

इसमें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर चिप का जटिल प्रारूप यानी जीपीयू, बहुकार्मिक क्षमता वाले विशालकाय प्रोग्राम यानी फाउंडेशनल माडल, भाषाओं के बहुत बड़े डाटा पर अभ्यास कराए गए लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम), महाकाय डाटा सेंटर आदि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। देश में सर्वम, कृत्रिम और भारतजेन नामक पूर्णतः स्वदेशी एलएलएम विकसित हुए हैं।

साथ ही सी डैक ने एआई स्टैक के रूप में ऐरावत नामक सुपर कंप्यूटर भी तैयार किया है। शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को आवश्यक गैर-व्यक्तिगत डाटासेट और माडल रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एआई कोश भी बनाया गया है। ये कदम सराहनीय हैं, पर अमेरिकी और चीनी कंपनियों के मुकाबले काफी छोटे हैं। भारत को एक-दो नहीं, बल्कि कई एलएलएम खड़े करने होंगे। आपसी प्रतिस्पर्धा इन माडल्स को धार और विस्तार देगी।

भारतीय परिदृश्य में दूसरे स्तर पर एप्लिकेशंस और माडल्स को ट्रेन करने के लिए डाटा की उपलब्धि एक बड़ी चुनौती है। संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित न करने वाला डाटा इन स्टार्टअप्स के साथ साझा करना सरल बनाना होगा। एआई या डाटा संप्रभुता को बड़े निवेश की दरकार है। उदाहरण के लिए एंथ्रोपिक ने पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष छह से सात अरब डालर खर्च किया है। ऐसे निवेश के लिए निजी एवं सरकारी सहयोग से धन जुटाना होगा। निवेश के अलावा संप्रभु एआई के लिए ऊर्जा भी एक बड़ी चुनौती बनेगी, जिसका प्रबंध सरकार को करना पड़ेगा।

नौकरशाही हस्तक्षेप को न्यूनतम रखते हुए विषय विशेषज्ञों की निगरानी में समय-समय पर सरकारी और बड़े निजी संस्थानों में एआई अंगीकरण और अनुवर्त्ती क्षमता विकास को मैप किया जाए। बहुत संभव है कि शुरुआती माडल अन्य बड़े माडलों के मुकाबले उतने परिपक्व न हों। चैटजीपीटी जैसे माडल भी प्रारंभिक अवस्था में इतने दक्ष नहीं थे। ऐसे में विचलित हुए बिना एआई संप्रभुता की ओर कदम बढ़ाने होंगे। संप्रभु एआई के लिए डाटा की संप्रभुता भी अनिवार्य है।

लगभग 135 देश डाटा रेजिडेंसी नामक अवधारणा के तहत अपने महत्वपूर्ण डाटा को देश में रखे सर्वरों पर ही रखना अनिवार्य करते हैं।

भारत को भी ऐसा करना चाहिए। एआई समिट में भारत सरकार द्वारा गूगल के साथ किए गए करार में ऐसी सुरक्षा शर्त रखनी चाहिए थी। गूगल द्वारा 15 अरब डालर का यह निवेश आर्थिक रूप से अवश्य लाभकारी है, पर इस सेंटर पर अभ्यास कराया गया भारतीय डाटा गूगल के ही स्वामित्व में रहेगा। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, इसलिए आयात-निर्यात के जिन नियमों की वजह से एंथ्रोपिक को अपने दो माडल हटाने पड़े, वह नियम जैमिनी पर भी लागू हो सकते हैं।

लीक से हटकर भारत कुछ ऐसा नया भी सोच सकता है, जिसमें विश्व में सबसे रचनात्मक और रोचक एआई इनोवेशन हब का निर्माण हो पाए और जिसमें विश्व के एआई उद्यमी निवेश करने में रुचि दिखाएं। चूंकि एआई एक नया पाठ्यक्रम है, इसलिए प्रयास होने चाहिए कि विश्व के सबसे अच्छे शिक्षकों से भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षण प्राप्त हो सके। भारत को अपने आप को ऐसे गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहिए, जो इस क्षेत्र के सर्वोत्तम मानव संसाधन को आकर्षित कर सके। ऐसे कई प्रसंग हैं जब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर लगी रोक के बाद भारत ने अपनी क्षमताओं को साबित किया।

क्रायोजेनिक इंजन, परम सुपर कंप्यूटर और परमाणु कार्यक्रम की सफलता ऐसे तीन बड़े उदाहरण हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा एंथ्रोपिक टूल्स पर प्रतिबंध को भी ऐसी ही एक चुनौती मानकर हमें संप्रभु एआई के लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए।

अभियान

घर का कबाड़ या दुर्भाग्य का द्वार? जानिए क्यों खाली डिब्बे और बोतलें तुरंत हटानी चाहिए

आधुनिक जीवनशैली ने हमारी आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और पैकेजिंग के बढ़ते चलन ने लगभग हर घर में प्लास्टिक के डिब्बों, कांच की बोतलों, कार्डबोर्ड बॉक्स और विभिन्न प्रकार के कंटेनरों का ढेर लगा दिया है। अधिकांश लोग यह सोचकर इन्हें संभालकर रख लेते हैं कि भविष्य में कभी न कभी इनका उपयोग हो जाएगा। धीरे-धीरे यह सामान अलमारी, स्टोर रूम, रसोई, बालकनी और घर के कोनों में जमा होता रहता है। देखने में यह एक सामान्य आदत लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान तीनों ही इस विषय पर गंभीर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यदि घर में लंबे समय तक बेकार और खाली वस्तुएँ बिना किसी उद्देश्य के रखी रहें, तो उनका प्रभाव केवल घर की सुंदरता पर ही नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक वातावरण पर भी पड़ सकता है।

वास्तु शास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा धारण करती है। घर में रखी हर वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। जब कोई वस्तु उपयोग में होती है तो उसकी ऊर्जा सक्रिय रहती है, लेकिन जब वही वस्तु लंबे समय तक खाली, टूटी या अनुपयोगी अवस्था में पड़ी रहती है, तो वह स्थिर ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिर ऊर्जा धीरे-धीरे घर के वातावरण को भारी बना देती है, जिससे परिवार के सदस्यों के विचार, व्यवहार और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

खाली डिब्बों और बोतलों को विशेष रूप से अभाव का प्रतीक माना जाता है। वे देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनका खालीपन अनजाने में घर के वातावरण में कमी और रुकावट का संकेत देता है। यही कारण है कि वास्तु शास्त्र में बार-बार यह सलाह दी जाती है कि घर में केवल वही वस्तुएँ रखें जिनकी वास्तविक आवश्यकता हो। अनावश्यक संग्रह न केवल स्थान घेरता है, बल्कि मानसिक बोझ भी बढ़ाता है। जिस प्रकार एक बंद कमरे में ताजी हवा का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार अत्यधिक कबाड़ से भरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बाधित होने लगता है।

भारतीय परंपरा में उत्तर-पूर्व दिशा को अत्यंत शुभ माना गया है। इसे ईशान कोण कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ज्ञान, समृद्धि तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में कबाड़, टूटा सामान या खाली कंटेनर रखने से शुभ ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए इस दिशा को हमेशा स्वच्छ, हल्का और खुला रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी कारणवश अतिरिक्त डिब्बे या कंटेनर रखना आवश्यक हो तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से दक्षिण या पश्चिम दिशा के स्टोर क्षेत्र में रखा जाना अधिक उचित माना जाता है।

मनोविज्ञान भी इस विषय पर रोचक तथ्य प्रस्तुत करता है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक सामान से भरा हुआ घर व्यक्ति के मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। जब चारों ओर बिखरी हुई वस्तुएँ दिखाई देती हैं तो मस्तिष्क लगातार उन्हें संसाधित करने में ऊर्जा खर्च करता है। परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि आजकल "डिक्लटरिंग" यानी अनावश्यक वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य सुधारने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। स्वच्छ और व्यवस्थित घर व्यक्ति को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा प्रदान करता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पुराने प्लास्टिक के डिब्बों और बोतलों का लंबे समय तक उपयोग उचित नहीं माना जाता। कई प्रकार के प्लास्टिक समय के साथ अपनी गुणवत्ता खोने लगते हैं और उनमें सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। यदि ऐसे पुराने कंटेनरों में भोजन या पानी रखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रखे गए खाली डिब्बों पर धूल, फफूंद और कीटाणु जमा हो सकते हैं, जो एलर्जी, श्वसन संबंधी समस्याओं और अन्य संक्रमणों का कारण बन सकते हैं। विशेषकर रसोईघर में स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही स्थान पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है।

बहुत से लोग कांच की खाली बोतलों को भी वर्षों तक संभालकर रखते हैं। यदि इनका कोई उपयोग नहीं है तो इन्हें पुनर्चक्रण के लिए भेज देना अधिक लाभदायक है। यदि रखना ही हो तो उनका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इनमें छोटे सजावटी पौधे या मनी प्लांट लगाकर घर की सजावट का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर घर में हरियाली और ताजगी का वातावरण भी बनता है। वास्तु की मान्यताओं में भी हरे पौधों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है।

आज "मिनिमलिस्ट" जीवनशैली पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। इसका मूल विचार यह है कि मनुष्य के पास केवल वही वस्तुएँ हों जिनकी वास्तव में आवश्यकता हो। कम सामान होने से घर अधिक व्यवस्थित रहता है, सफाई आसान होती है और मानसिक शांति भी बढ़ती है। भारतीय संस्कृति में भी "अपरिग्रह" अर्थात अनावश्यक संग्रह न करने का सिद्धांत हजारों वर्षों से बताया गया है। यह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का भी महत्वपूर्ण नियम है।

हालाँकि यह समझना भी आवश्यक है कि वास्तु शास्त्र की मान्यताएँ पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं। आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य या पारिवारिक सुख केवल खाली डिब्बे हटाने से ही निर्धारित नहीं होते। इनके पीछे मेहनत, अनुशासन, आर्थिक योजना, स्वच्छता, सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग जैसे अनेक व्यावहारिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तु के सिद्धांतों का पालन करना चाहता है, तो उसे इन्हें जीवन की अच्छी आदतों—जैसे नियमित सफाई, अनावश्यक वस्तुओं का पुनर्चक्रण, व्यवस्थित जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों—के साथ जोड़कर अपनाना चाहिए।

दरअसल, घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी इमारत नहीं होता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की ऊर्जा, भावनाओं और जीवनशैली का प्रतिबिंब होता है। जब घर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अनावश्यक वस्तुओं से मुक्त होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों के मन में भी हल्कापन और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इसलिए समय-समय पर अपने घर का निरीक्षण करें, उन वस्तुओं को अलग करें जिनका महीनों या वर्षों से कोई उपयोग नहीं हुआ है और उन्हें दान, पुनर्चक्रण या उचित तरीके से निस्तारित कर दें। इससे न केवल घर अधिक सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा, बल्कि स्वच्छ वातावरण, बेहतर मानसिक स्थिति और संतुलित जीवनशैली की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

Vibrant GUJARAT REGIONAL CONFERENCES
Regional Aspirations, Global Ambitions

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

मध्य गुजरात

29th | 30th JUNE 2026

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ

प्रमुख क्षेत्र

- सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
- केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स
- ग्रीन एनर्जी ईकोसिस्टम
- ऑटो और ऑटो कम्पोनेंट्स
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
- एयरोस्पेस और डिफेंस
- पर्यटन और संस्कृति
- स्टार्टअप्स और MSMEs
- IT और ITeS
- बायोटेक
- फ़ार्मास्युटिकल्स
- फ़िनटेक
- कौशल विकास
- एजुकेशन

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

- उद्घाटन समारोह
- पैनल डिस्कशन्स
- B2B/B2G मीटिंग्स
- क्षेत्र-विशिष्ट सेमिनार
- राउन्ड टेबल सम्मेलन
- विशेष दौरे/औद्योगिक दौरे
- कंट्री सेमिनार
- रिवर्स बायर-सेलर मीटिंग
- विक्रेता विकास कार्यक्रम
- क्षेत्रीय पुरस्कार (MSMEs/आर्टिज़न)
- उद्यमी मेला
- समापन सत्र
- क्षेत्रीय MSME सम्मेलन
- ट्रेड शो/प्रदर्शनी

माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल जी
द्वारा शुभारंभ

गरिमामय उपस्थिति
श्री मनोहर लाल
माननीय केंद्रीय मंत्री, विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार

श्री हर्ष संघवी
माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

29 जून 2026, सोमवार | सुबह 10:30 बजे
GSFC युनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात

''वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से गुजरात के औद्योगिक उत्कर्ष की नई दिशा खुलेगी।''
-हर्ष संघवी, उपमुख्यमंत्री, गुजरात

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एक्ज़ीबिशन 29 जून से 3 जुलाई, 2026 | सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

वेबसाइट के लिए स्कैन करें

भागीदार देश: Japan, Rwanda, UAE, Ukraine

भागीदार संस्थाएँ: JETRO, US-INDIA, Trade Representation of the Russian Federation, AMCHAM INDIA, FEBI, IICCI, FINCHAM INDIA Finland Chamber of Commerce in India, kotra Korea Trade-Investment Promotion Agency, icbc INDO CANADIAN BUSINESS CHAMBER, U.S.-India Business Council, UIBC, ACMA

सीधा प्रसारण: CMOGuj | CMOGuj | CMOGujarat | CMOGujarat | vibrantgujarat | vibrantgujarat | vibrant_gujarat | vibrantgujarat

कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए स्कैन करें

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगीत नाटक अकादमी के 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार' के लिए गुजरात की त्विषा व्यास का चयन

गांधीनगर : बारडोली, दक्षिण गुजरात का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर, जहां शाम ढलते ही गरबे की धुन गूंजने लगती है। इसी शहर के एक प्रशिक्षण केंद्र में युवा लड़कियां पूरे उत्साह और लगन के साथ गरबा सीख रही हैं। एक युवा कलाकार लड़कियों को धैर्य के साथ गरबा के हर हावभाव, हर ताल और हर स्टेप की बारीकियां समझाती है, इस युवा कलाकार का नाम है- सुश्री त्विषा किल्लोल कुमार व्यास।

केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2025 के 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार' के लिए गुजरात के लोकनृत्य 'गरबा' के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुश्री त्विषा व्यास का चयन किया है।

त्विषा व्यास को यह सम्मान ऐसे समय में मिला है, जब कुछ वर्ष पहले ही यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में शामिल किया है।

गरबा केवल लोकनृत्य ही नहीं, एक जीवन दर्शन भी है

बारडोली में वी. किल्लोल कुमार ग्रुप ऑफ म्यूजिक एंड नृत्य की संचालक सुश्री त्विषा व्यास के अनुसार, "गरबा आस्था, संस्कृति और सामूहिक पहचान की एक जीवंत अभिव्यक्ति है।" त्विषा व्यास की यही सोच उनकी कला यात्रा का आधार बनी। ज्यादातर लोग गरबे को एक लोकनृत्य के रूप में सीखते हैं, लेकिन त्विषा व्यास ने गरबे के मूल स्वरूप, परंपरा, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक अर्थ को समझने के लिए साधना की।

त्विषा व्यास : गरबा के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य और संगीत-नृत्य में भी निपुण

त्विषा व्यास की पहचान केवल लोकनृत्य तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही, वे एक अच्छी वायलिन वादक भी हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, श्री आनंद जी कल्याण के समक्ष अपनी वायलिन वादन की कला का प्रदर्शन किया है। वे मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (एमपीए) तथा भरतनाट्यम में एमए-'अलंकार' के साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। वे वायलिन के अलावा मेंडोलिन, बांसुरी, हारमोनियम और तबला जैसे अनेक वाद्यों में भी निपुण हैं। नृत्य और संगीत, दोनों क्षेत्रों में प्राप्त इस व्यापक प्रशिक्षण ने त्विषा व्यास को लय, अभिव्यक्ति और प्रस्तुति की एक विशिष्ट समझ दी है। उन्होंने संगीतकार के रूप में अपने अनुभव को गरबा में जोड़ा है, जो उनकी गरबे की हर प्रस्तुति में झलकता है।

त्विषा व्यास ने गुजरात सरकार की ओर से आयोजित होने वाले अनेक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिनमें तरणेतर का मेला, चोटिला उत्सव, मोढेरा उत्सव, डाकोर फागणोत्सव, वसंतोत्सव, जी-20, गुजरात गौरव अभियान और अंबाजी महोत्सव आदि शामिल हैं। वे कला महाकुंभ और युवा उत्सव जैसी सरकार की विभिन्न प्रतियोगिताओं में एक निर्णायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने गुजरात की सीमाओं को पार कर राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गुजरात के गरबा और लोकसंस्कृति का प्रतिनिधित्व कर राज्य का गौरव बढ़ाया है।

विरासत के संवर्धन की सामूहिक जिम्मेदारी

त्विषा व्यास के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान उनकी कला यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। उनका मानना है कि नई पीढ़ी को गरबा को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जीवंत सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना चाहिए। इसकी पवित्रता और मूल परंपरा को बनाए रखने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। त्विषा व्यास के इस विचार का महत्व आज और भी बढ़ जाता है, खासकर जब परंपरागत कलाएं आधुनिक जीवन शैली और व्यावसायिक मनोरंजन के बीच अपना स्थान बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में, त्विषा व्यास जैसे युवा कलाकार परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दिखाता है कि आधुनिकता के बीच भी विरासत का संरक्षण करना कठिन नहीं है।

गुजरात की लोककला का सम्मान

त्विषा व्यास की यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह गुजरात की समृद्ध लोकसंस्कृति का सम्मान है। आज, जब लोकप्रियता को सफलता का पैमाना माना जाता है, तब त्विषा व्यास का सफर शांत और निरंतर साधना, वर्षों की मेहनत और संस्कृति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की अलग ही कहानी कहता है।

बारडोली के गरबा चौक से देश के सर्वोच्च युवा कला सम्मान तक, त्विषा व्यास का सफर हमें याद दिलाता है कि परंपराएं तभी जीवंत रहती हैं, जब नई पीढ़ी केवल उसे विरासत में प्राप्त ही नहीं करती, बल्कि उसे गौरवपूर्वक आगे भी बढ़ाती है। और शायद, इसी प्रकार संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार होता है।

गुजरात का 2030 तक देश में बायोटेक्नोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग का हब बनने का लक्ष्य

▶▶ लक्ष्य को हासिल करने में फार्मा और केमिकल क्षेत्रों की अहम भूमिका

▶▶ जीआरआईटी की रिपोर्ट में भारत की बायोमैन्युफैक्चरिंग क्रांति का नेतृत्व करने के लिए गुजरात के विजन को प्रस्तुत किया गया

गांधीनगर : गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात 2030 तक कुशल मानवबल विकास, विशेष शिक्षा और उद्योग-उन्मुख कौशल निर्माण पर केंद्रित महत्वाकांक्षी रणनीति की मदद से भारत के बायोटेक्नोलॉजी (जैव प्रौद्योगिकी) और बायोमैन्युफैक्चरिंग (बायो-विनिर्माण) क्षेत्र का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

'गुजरात बायो-इकोनॉमी 2030 : स्ट्रैटेजिक स्किल आर्किटेक्चर एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बायो-इकोनॉमी 2014 में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 150 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार की बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के समर्थन से देश ने दशक के अंत तक यानी 2030 तक 300 अरब डॉलर की बायो-इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें गुजरात की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात आगामी वर्षों में देश के बायो-इकोनॉमी क्षेत्र में एक शीर्ष राज्य के रूप में उभरने के लिए तैयार है। अभी भारत के कुल फार्मास्युटिकल उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है और यह देश के अग्रणी केमिकल उत्पादन केंद्रों में से एक बना हुआ है।

भारत का रणनीतिक लक्ष्य : 300 अरब डॉलर की बायो-इकोनॉमी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बायो-इकोनॉमी ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। 2014 में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में यह 150 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। 2030 तक 300 अरब डॉलर की बायो-इकोनॉमी का राष्ट्रीय लक्ष्य केवल एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि स्थानीय मांग और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया आर्थिक आयोजन है।

वृद्धि को गति देने वाले मुख्य उप-क्षेत्र इस प्रकार हैं :

बायोफार्मा (35%) : इसमें वैक्सीन, थेराप्युटिक्स और डाइग्नोस्टिक्स का वर्चस्व है। भारत दुनिया भर में विभिन्न वैक्सीनों की कुल मांग का 35 फीसदी से अधिक हिस्सा सप्लाई करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (एमआरएनए) और वायरल वेक्टर जैसी नई टेकनोलॉजी के विकास के साथ यह क्षमता और बढ़ने की संभावना है।

बायो-इंडस्ट्रियल (47%) : इथेनॉल मिश्रण (20% का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया गया) और बायो-आधारित रसायनों के बढ़ते उपयोग के कारण फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

बायो-एग्रीकल्चर (8%) : जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी होने के कारण क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेहस्डक शॉर्ट पैलिनड्रॉमिक रिपीट्स (सीआरआईएसपीआर) आधारित फसल और बायो-फर्टिलाइजर जैसी टेकनोलॉजी अब प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंच रही हैं। केंद्र सरकार की बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) में उच्च कुशल बायोमैन्युफैक्चरिंग के लिए कुशल मानवबल की जरूरत पर विशेष जोर दिया गया है। नीति के डॉक्यूमेंट के अनुसार, योग्य प्रतिभा और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षमता का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

गुजरात के नीति निर्धारण में रणनीतिक बदलाव : औद्योगिक शक्ति से बायो-इकोनॉमी की ओर

गुजरात को देश का अहम औद्योगिक राज्य माना जाता है। गुजरात भारत के कुल फार्मास्युटिकल उत्पादन में लगभग 40 फीसदी का योगदान देता है और यह केमिकल प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 राज्य की औद्योगिक क्षमता को बायो-इकोनॉमी में रूपांतरित करने की एक स्पष्ट दिशा दिखाती है। राज्य का लक्ष्य केवल जेनरिक दवाइयों के उत्पादन से आगे बढ़कर इनोवेटिव बायोलॉजिक्स के विकास में आगे बढ़ना है।

'जीआरआईटी-ग्रिट' की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के पास औद्योगिक विकास का आधार, विशाल उत्पादक क्षमता, अनुसंधान संस्थान, प्रगतिशील नीतियां, 1600 किमी लंबी तटरेखा और विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र जैसे सभी आवश्यक कारक उपलब्ध होने के कारण राज्य वैश्विक बायो-इकोनॉमी के क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है।

नई संभावनाएं

रिपोर्ट के अनुसार, 300 अरब डॉलर की बायो-इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में मजबूत स्थानीय टैलेंट इकोसिस्टम विकसित करने का बड़ा अवसर है। इससे अन्य प्रतिभा पलायन कम होगी तथा कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देने की जरूरत भी कम होगी। विशेष शिक्षा और कौशल विकास के जरिए राज्य की क्षमता में वृद्धि करके टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

मजबूत अकादमिक आधार

गुजरात में बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़े पाठ्यक्रम चलाने वाले 23 संस्थानों के व्यापक अध्ययन से राज्य के शिक्षा क्षेत्र के मजबूत आधार और उसकी खास क्षमताएं सामने आई हैं। यह विश्लेषण दिखाता है कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करने में सक्षम है। साथ ही, उभरते उद्योग रुझानों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों को अधिक सुसंगत बनने के विशाल अवसर भी उपलब्ध हैं, ताकि भविष्य की बायोटेक्नोलॉजी जरूरतों के अनुरूप कुशल युवा तैयार किए जा सकें।

सरकार और गुजरात राज्य हस्तशिल्प एवं हस्तकला विकास निगम के प्रयासों से पारंपरिक फर्नीचर कला को मिल रही नई ऊंचाई

▶▶ संखेड़ा की पारंपरिक कला को मिली नई पहचान, कारीगरों के विकास को मिला नया मार्ग

▶▶ VGRC-मध्य गुजरात 2026 में वैश्विक स्तर पर चमकेगी संखेड़ा फर्नीचर की पहचान

गांधीनगर, 28 जून : गुजरात की पारंपरिक हस्तकलाओं में संखेड़ा फर्नीचर का एक विशिष्ट स्थान है। लकड़ी पर की जाने वाली रंगीन लाख कला और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध संखेड़ा फर्नीचर अब केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न शहरों और विदेशी बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस परिवर्तन के पीछे सरकार तथा गुजरात राज्य हस्तशिल्प एवं हस्तकला विकास निगम के निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में 29 और 30 जून, 2026 को आयोजित होने वाला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) - मध्य गुजरात 2026 केवल निवेश और औद्योगिक विकास का मंच ही नहीं, बल्कि गुजरात की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय उद्योगों को नए बाजारों से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। इन प्रयासों में विश्व प्रसिद्ध संखेड़ा फर्नीचर का महत्वपूर्ण स्थान है, जो आज गुजरात की परंपरा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

क्या है संखेड़ा फर्नीचर की विशेष पहचान?

संखेड़ा फर्नीचर वडोदरा के निकट स्थित संखेड़ा गांव की पारंपरिक लकड़ी की हस्तकला है। मुख्य रूप से खाराड़ी कारीगर समुदाय पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए है। मान्यता के अनुसार लगभग 200 वर्ष पूर्व संखेड़ा आए एक संत ने स्थानीय बढ़ई परिवारों को लकड़ी के फर्नीचर पर लाख और कलई से सजावटी डिजाइन बनाने की कला सिखाई थी। तभी से यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही है।

पारंपरिक कारीगरों को बाजार से जोड़ने, उनकी कला को प्रोत्साहित करने तथा नई पीढ़ी को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए निगम द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। कारीगरों को प्रदर्शनियों, मेलों और विभिन्न विपणन मंचों के माध्यम से अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से उनकी कौशल क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

कहां और कैसे तैयार होता है यह फर्नीचर?

यह हस्तकला मुख्य रूप से संखेड़ा तथा वडोदरा और छोटाउदेपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। खाराड़ी बढ़ई समुदाय के कारीगर पारंपरिक औजारों और लेथ मशीन की सहायता से लकड़ी को आकार देते हैं। इसके बाद हाथ से डिजाइन पेंटिंग, लाख की परत और पॉलिश का कार्य किया जाता है।

एक फर्नीचर तैयार करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। झूले, पाटला, कुर्सियां, सोफा सेट, बच्चों के पालने तथा डाइनिंग टेबल जैसी अनेक वस्तुओं में इस कला की विशेष झलक देखने को मिलती है। प्रत्येक उत्पाद में कारीगरों की मेहनत, अनुभव और पीढ़ियों से प्राप्त कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। आज संखेड़ा फर्नीचर को जीआई टैग प्राप्त होने से इसकी विशिष्ट पहचान और भी मजबूत हुई है।

कारीगरों की आय में लगभग 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि

निगम द्वारा कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, नई उत्पादन तकनीकों और विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप वे बाजार की बदलती मांग के अनुरूप अधिक आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इन प्रयासों से कारीगरों की आय में लगभग 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। संखेड़ा फर्नीचर की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विभिन्न हस्तकला मेलों, एक्सपो और प्रदर्शनियों में इसे प्रमुख स्थान दिया गया है। अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नए ग्राहकों तक पहुंच का मार्ग खुला है। इसके अतिरिक्त एम्पोरियम तथा अन्य बिक्री माध्यमों के जरिए प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था भी विकसित की गई है। वर्तमान में लगभग 3 संखेड़ा फर्नीचर कारीगर सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं, जबकि हजारों लोग परोक्ष रूप से इस पारंपरिक हस्तकला आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

आज संखेड़ा फर्नीचर की मांग अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी इसकी पहुंच मजबूत हुई है। पारंपरिक झूले, कुर्सियां, सोफा सेट और गृह सज्जा के अन्य उत्पाद ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि युवा पीढ़ी को इस कला से अधिक सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए आधुनिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और नवाचार आधारित उत्पादों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स तथा अनुभव आधारित प्रदर्शनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

आज संखेड़ा फर्नीचर केवल एक पारंपरिक हस्तकला नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कारीगर सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सशक्त माध्यम बन चुका है। VGRC - मध्य गुजरात 2026 जैसे मंचों के माध्यम से इस कला को निवेशकों, खरीदारों और वैश्विक बाजारों से जोड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार के सतत प्रयासों से संखेड़ा फर्नीचर 'लोकल टू ग्लोबल' के विजन को साकार करते हुए आत्मनिर्भर भारत और विकसित गुजरात के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अध्ययन का दावा: उच्च शिक्षा वाले देशों में धर्म का महत्व घट रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। विश्व के अविकसित और गरीब देशों में धर्म अधिक प्रचलित हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इथियोपिया आदि। जिन देशों में शिक्षा का अभाव है, वहां धर्म अधिक प्रचलित है।

दूसरी ओर, विकसित देशों में जहाँ शिक्षा का स्तर उच्च है, वहाँ बुद्धिजीवियों और शिक्षित लोगों की संख्या अधिक है। क्योंकि बुद्धिजीवी विशेष रूप से धर्मों के प्रभाव से दूर रहते हैं। इस संबंध में विश्व स्तर पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, कनाडा में 73%, स्पेन में 78%, फ्रांस में 88%, नॉर्वे में 81% और ऑस्ट्रेलिया में 82% लोग अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं।

लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं, जब इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन में 90% लोग धर्मों से दूर होते जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं: विज्ञान और शिक्षा। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें, तो विज्ञान अब उन सवालों के सही जवाब दे रहा है जिनका जवाब पहले धर्म में दिया जाता था। क्योंकि पहले

जब पूछा जाता था कि बारिश कैसे होती है, तो धर्म कहता था कि इंद्र देवता बारिश करवा रहे हैं। जब विज्ञान ने इस विषय पर शोध किया और सही जवाब दिया, तो शिक्षित लोगों का धर्म के प्रति भ्रम दूर हो गया। बारिश के बारे में की जाने वाली पूजा-अर्चना का सिलसिला टूट गया।

यदि धर्म ब्रह्म पर आधारित था और उसी से परिपूर्ण था, तो विज्ञान और शिक्षा के कारण अब उसका अंत हो रहा है। अब यदि हम शिक्षा की बात करें, तो बुद्धिमान लोग भी यह देख रहे हैं कि समाज में नैतिकता का संबंध शिक्षा से है, न कि धर्म से। जैसे अतीत में, देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और मनुष्यों की बलि दी जाती थी, जो एक अनैतिक कार्य था। और यह सब धर्म के नाम पर किया जाता था। फिर जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा और समझ विकसित हुई, ऐसी कई प्रथाएँ बंद होने लगीं। और एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि जिन देशों में शिक्षा का स्तर उच्च है, वहाँ धर्म का प्रचलन कम है। अपराध दर भी कम है और नैतिकता का स्तर भी उच्च है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म गरीब और पिछड़े देशों में अधिक प्रचलित है। अर्थात्, गरीबी और धर्म के बीच एक अटूट संबंध है। और इसी कारण यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि कोई गरीब देश धर्म के कारण गरीब है या गरीबी के कारण धार्मिक है? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है।

प्रेस्टीज एस्टेट्स ने रचा नया कीर्तिमान: 65 हजार करोड़ रुपये का अनरियलाइज्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड बिक्री से रियल एस्टेट सेक्टर में नई उम्मीद

नई दिल्ली। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उद्योग जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी ने न केवल रिकॉर्ड स्तर की बिक्री दर्ज की है, बल्कि उसका अनरियलाइज्ड (गैर-मान्यता प्राप्त) राजस्व लगभग 65,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में कंपनी के पास बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होने की संभावना है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हो सकती है।

रियल एस्टेट उद्योग में अनरियलाइज्ड रेवेन्यू का अर्थ उन परियोजनाओं की बिक्री से है जिनकी बुकिंग तो हो चुकी है, लेकिन निर्माण पूरा न होने या लेखांकन मानकों के कारण उस बिक्री को अभी तक कंपनी की आधिकारिक आय में शामिल नहीं किया गया है। जैसे-जैसे परियोजनाएं पूरी होंगी और ग्राहकों को संपत्तियों का कब्जा सौंपा जाएगा, यह राशि चरणबद्ध तरीके से कंपनी के राजस्व में शामिल होती जाएगी। इसलिए 65 हजार करोड़ रुपये का यह आंकड़ा केवल एक वित्तीय संख्या नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत आय का संकेत भी माना जा रहा है।

कंपनी ने जानकारी दी कि यह उपलब्धि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आवासीय परियोजनाओं की जबरदस्त मांग और निरंतर बिक्री के कारण संभव हुई है। देश के विभिन्न महानगरों में कंपनी की लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग परियोजनाओं को खरीदारों से अच्छा प्रतिसाद मिला है। विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे, एनसीआर और अन्य प्रमुख शहरों में कंपनी की परियोजनाओं की बिक्री लगातार बढ़ी है।

वित्त वर्ष 2025-26 में प्रेस्टीज एस्टेट्स ने 30,024 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। यह कंपनी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बिक्री है। इस रिकॉर्ड वृद्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊंची ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में गुणवत्तापूर्ण आवासीय परियोजनाओं की मांग मजबूत बनी हुई है।

कंपनी के चेयरमैन इरफान रजाक ने कहा कि कंपनी के बही-खाते में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये का अनरियलाइज्ड रेवेन्यू मौजूद है, जो आने वाले वर्षों में कंपनी की आय का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने इसे कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ग्राहकों का विश्वास और परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में कंपनी 'कंप्लीशन मेथड' के आधार पर राजस्व की गणना करती है। इस पद्धति में तब तक राजस्व को मान्यता नहीं दी जाती जब तक परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। हालांकि कंपनी अब 'परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड' अपनाने की संभावना पर अपने ऑडिटर्स के साथ विचार-विमर्श कर रही है। इस पद्धति के तहत निर्माण कार्य जितना पूरा होता है, उसी अनुपात में राजस्व को भी दर्ज किया जाता है। यदि भविष्य में यह बदलाव लागू होता है तो कंपनी के वित्तीय परिणामों में राजस्व और लाभ का स्वरूप अलग दिखाई दे सकता है तथा निवेशकों को परियोजनाओं की प्रगति का अधिक वास्तविक चित्र मिल सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महामारी के बाद लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है और बड़े घरों, आधुनिक सुविधाओं तथा सुरक्षित आवासीय परिसरों की मांग तेजी से बढ़ी है। साथ ही शहरीकरण, आय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के नए अवसरों ने भी आवासीय बाजार को गति दी है। ऐसे माहौल का सबसे अधिक लाभ उन कंपनियों को मिला है जिनकी बाजार में विश्वसनीयता मजबूत है और जो समय पर परियोजनाएं पूरी करने के लिए जानी जाती हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी ऐसी ही कंपनियों में शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से राज्यव्यापी पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया

▶▶ 'पोलियो उन्मूलन अभियान' के तहत राज्य के 0 से 5 वर्ष की आयु के 83.49 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी

▶▶ स्वास्थ्यकर्मी 29 और 30 जून के दौरान घर-घर जाकर पिलाएंगे वैक्सीन की बूंदें

▶▶ स्वास्थ्य विभाग के 6599 सुपरवाइजर्स के मार्गदर्शन में 65,994 स्वास्थ्य टीमें पल्स पोलियो अभियान चलाएंगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पोलियो उन्मूलन के लिए 'पल्स पोलियो अभियान' के अंतर्गत रविवार को गांधीनगर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो रोधी टीकाकरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया।

इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 0 से 5 वर्ष की आयु के 83 लाख 49 हजार से अधिक बच्चों को कवर किया जाएगा। इस उद्देश्य से, पूरे राज्य में 32,997 पोलियो बूथों पर स्वास्थ्य विभाग के 6599 सुपरवाइजरों के मार्गदर्शन में कुल 65,994 स्वास्थ्य टीमें बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के काम में जुटेंगी।

रविवार, 28 जून 2026 को 'पोलियो रविवार' के रूप में मनाकर यह अभियान शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी हाउस टू हाउस यानी घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष की आयु के शिशुओं को पोलियो रोधी वैक्सीन की बूंदें पिलाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानसेरिया की उपस्थिति में बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की बूंदें पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष दवे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. रतन कंवर गढ़वी और बच्चों के माता-पिता सहित स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे।

वडोदरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कम दूरी की कुछ ट्रेन निरस्त, दादर – एकतानगर - दादर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस वडोदरा स्टेशन पर होगी शॉर्ट टर्मिनेट / शार्ट ओरिजनेट

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा स्टेशन पर व्यापक यार्ड रीमॉडलिंग एवं ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का कार्य अब अंतिम चरण पर है। इसी क्रम में दिनांक 30 जून 2026 को वडोदरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जायेगा। फलस्वरूप कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य परिचालन संरक्षा में वृद्धि, लाइन एवं प्लेटफॉर्म क्षमता का विस्तार, ट्रेन संचालन दक्षता में सुधार तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।यात्रियों को इंफ्रा के इस महत्वपूर्ण कार्य में न्यूनतम असुविधा हो इस बात का वडोदरा मंडल द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की कम दूरी की कुछ ट्रेनें पूर्णतः निरस्त रहेंगी एवं 3 ट्रेनें शोर्ट टर्मिनेट / शोर्ट ओरिजिनेट होगी, जो इस प्रकार है:

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 59549 वडोदरा–वटवा पैसेंजर

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 59550 वटवा–वडोदरा पैसेंजर

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 79440 कथाना-प्रतापनगर डेमू

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 79439 प्रतापनगर–कथाना डेमू

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 79461 मियागाम करजन–प्रतापनगर डेमू

▶▶ 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 79462 प्रतापनगर-मियागाम करजन डेमू

▶▶ 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 22930 वडोदरा-दहानू रोड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

▶▶ 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 22929 दहानू रोड–वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस

▶▶ 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 19011 वलसाड-दाहोद एक्सप्रेस

▶▶ 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 19012 दाहोद-वलसाड एक्सप्रेस

शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन ट्रेनें :-

* 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 12929 वलसाड – वडोदरा इंटरसिटी, विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

* 29,30 जून एवं 01 जुलाई 2026 की ट्रेन संख्या 69110 वडोदरा–भरूच मेमू मकरपुरा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा वडोदरा–मकरपुरा के बीच निरस्त रहेगी।

* 29,30 जून 2026 को दादर से चलने वाली ट्रेन संख्या 12927 दादर – एकतानगर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस वडोदरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी तथा वडोदरा– एकतानगर के बीच निरस्त रहेगी।

* 30 जून एवं 01 जुलाई 2026 को एकतानगर से चलने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकतानगर -दादर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस वडोदरा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी तथा एकतानगर – वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।